RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 307
दि. 11.03.2026, बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का मेगा प्लान

सभी विधायकों से मांगे गए 5-5 करोड़ रुपये तक के विकास प्रस्ताव

चुनावी साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगें हैं. मुख्यमंत्री ने 5-5 करोड़ रुपए के विकास प्रस्ताव को एक हफ्ते में देने का निर्देश दिया हैं. यह प्रस्ताव विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों से मांगे गए हैं.

लखनऊ. (जीएनएस)। उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को तेज गति देने और विधायकों के क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्देश जारी किया है. सीएम ने सभी विधायकों से अपने-अपने क्षेत्र में 5-5 करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे हैं. इन प्रस्तावों को एक सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय भेजना अनिवार्य होगा.

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विधायक अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं जैसे सड़क, जल निकासी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास कार्यों पर फोकस करें. प्रस्ताव भेजने के बाद संबंधित जिलाधिकारियों

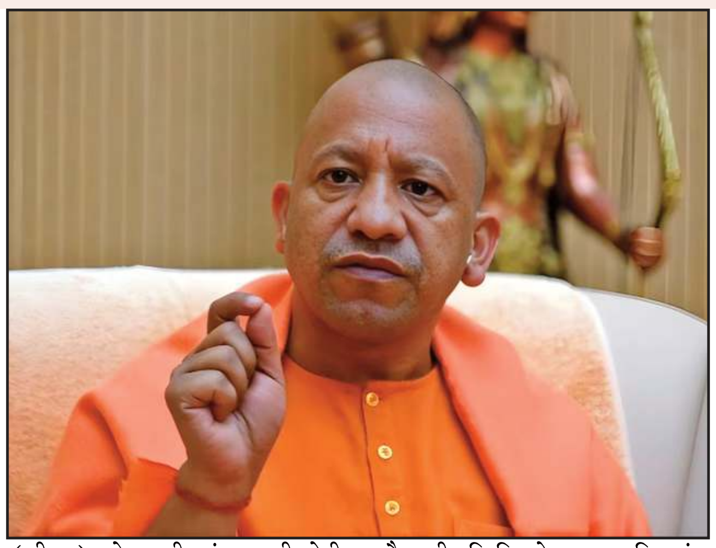

(डीएम) को इनकी जांच करनी होगी और स्वीकृति मिलने पर धनराशि तुरंत जारी की जाएगी. सीएम ने सभी विधायकों को निर्देश दिया है कि वे क्षेत्र में रहकर इन विकास कार्यों की निगरानी खुद करें, ताकि कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे हों.

खास बात यह है कि सरकार ने पहली बार विधान परिषद सदस्यों (एमएलसी) से भी ऐसे प्रस्ताव मांगे हैं. इससे विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों के सदस्यों को अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कराने का अवसर मिलेगा. प्रस्तावों को विभिन्न विकास योजनाओं में शामिल किया जाएगा ।

और एसआईआर (सिस्टेमेटिक इंटीग्रेटेड रजिस्ट्रेशन) प्रक्रिया के तहत अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा.

यह कदम प्रदेश में विकास की गति बढ़ाने और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता तक पहुंच मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मुख्यमंत्री का जोर है कि विकास कार्यों से क्षेत्र की समस्याओं का स्थायी समाधान हो और जनता को ठोस लाभ मिले. प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि एक सप्ताह तय की गई है, जिसके बाद

प्रधानमंत्री ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर उन्हें बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के स्थापना दिवस पर सभी कर्मियों को बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि दृढ़ संकल्प, अनुशासन और समर्पण के लिए प्रसिद्ध, सीआईएसएफ देशभर में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता भारत की सुरक्षा और प्रगति में महत्वपूर्ण

योगदान देती है।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखाः

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सभी कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं।

अपने दृढ़ संकल्प, अनुशासन और समर्पण के लिए प्रसिद्ध, सीआईएसएफ पूरे देश में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता भारत की सुरक्षा और प्रगति में बहुत बड़ा योगदान देती है।

पश्चिम एशिया की स्थितिः भारतीय विमानन कंपनियां 12 मार्च से और जगहों के लिए सेवाएं देंगी

नागर विमानन मंत्रालय पश्चिम एशिया क्षेत्र में चल रहे घटनाक्रमों और भारत और इस क्षेत्र के बीच हवाई यातायात पर इसके संभावित असर पर कड़ी नजर रख रही है। नागर विमानन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं और सभी संबंधित हितधारकों के साथ सीधे संपर्क में हैं ताकि जल्दी और मिलकर जवाब प्रतिक्रिया दी जा सके। एयरलाइंस बदलती स्थिति के हिसाब से सही परिचालन इंतजाम कर रही हैं, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा और सेवाएं जारी रखना सबसे जरूरी है।

9 मार्च 2026 के ऑपरेशनल डेटा से पता चलता है कि इंडियन कैरियर्स द्वारा ऑपरेट की गई 45 इनबाउंड फ़्लाइट्स वेस्ट एशिया से भारत आईं, जिनमें 7,407 यात्री थे। भारतीय कैरियर्स ने भी यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही और जरूरत पड़ने पर निकासी समर्थन सुनिश्चित करने के लिए परिचालन लचीलेपन की मांग की है। डीजीसीए ने अतिरिक्त आगमन और प्रस्थान के स्लॉट की सुविधा देने और दुबई, जेद्दा और मदीना जैसी जगहों के लिए उड़ानों के रास्ते में एक वैकल्पिक हवाई अड्डे के तौर पर मस्कट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के इस्तेमाल की इजाजत देने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वयन किया है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशेष स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया

(जीएनएस)।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आज अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक विशेष जागरूकता सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं के स्वास्थ्य सशक्तिकरण और मानसिक कल्याण के दोहरे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी गईं।

स्वास्थ्य एवं मानव संसाधन मंत्रालय (डीएचआर-आईसीएमआर) के साक्ष्य-आधारित दिशानिर्देश केंद्र में वैज्ञानिक एफ डॉ. चंचल गोयल ने महिला सशक्तिकरण, विज्ञान में महिलाएं और महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता शीर्षक पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता सामाजिक प्रगति की नींव हैं। डॉ. गोयल ने महत्वपूर्ण निवारक स्वास्थ्य उपायों, विशेष रूप से एचपीवी टीकाकरण और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से निपटने के लिए नियमित जांच (पैप स्मीयर) के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि स्वास्थ्य जागरूकता ही वास्तविक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण घटक है।

मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के अक्सर उपेक्षित पहलू का उल्लेख करते हुए, सेंटर फॉर एविडेंस-बेस्ड गाइडलाइंस (डीएचआर) के डॉ. विकास धिकाव ने "महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य" विषय पर प्रस्तुति दी। उनके सत्र में महिलाओं को जीवन के विभिन्न

चरणों में सामना करने वाले विशिष्ट जैविक और सामाजिक तनावों का विस्तार से वर्णन किया गया।

डॉ. धिकाव ने कर्मचारियों से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को तोड़ने का आग्रह किया और संतुलित एवं उत्पादक जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप, तनाव प्रबंधन और मजबूत सहायता प्रणालियों को बनाए रखने के महत्व पर बल दिया।

संस्थागत प्रतिबद्धता

यह आयोजन समावेशी कार्यस्थल को बढ़ावा देने और अपने कर्मचारियों के समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करने के प्रति मंत्रालय की निरंतर प्रतिबद्धता को दशार्ता है। वैज्ञानिक चर्चा को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के साथ एकीकृत करके, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अपनी महिला वैज्ञानिकों और पेशेवरों को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदान देने के लिए सशक्त बनाना जारी रखता है।

इस कार्यक्रम में डॉ. कमलजीत रे (वैज्ञानिक जी), श्री विनोद कुमार (निदेशक), डॉ. जगवीर सिंह (वैज्ञानिक जी) और डॉ. प्रवीण कुमार (वैज्ञानिक जी) सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

तेल-गैस को लेकर देश में क्या है हाल? एक्शन में पीएम मोदी, कहा- घबराएं नहीं, धड़ाधड़ दिए ये आदेश

पश्चिम एशिया में जंग छिड़ने से दुनियाभर में एनर्जी का संकट दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत में ऑयल और गैस की कोई किल्लत नहीं है. भारत में पर्याप्त आपूर्ति बनी हुई है. हालांकि, एहतियात के तौर पर भारत ने कई कदम उठाए हैं.

नई दिल्ली, (जीएनएस)।

ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच चल रही जंग ने दुनिया भर में एनर्जी संकट को पैदा कर दिया है. खासकर LPG सप्लाई को लेकर स्थिति बिगड़ी है. भारत भी इसे लेकर अलर्ट है. भारत में LPG की कमी नहीं है, लेकिन भविष्य की संभावनाओं के कारण पैनिक सिचुएशन बन चुका है.

कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में तेज बढ़ोतरी देखी गई है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, सिलेंडर की जमाखोरी होने से LPG सिलेंडर ज्यादा दाम पर दिए जा रहे हैं. इन्हीं सभी चीजों को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई.

देशवासियों पर नहीं पड़े असर

कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों को निर्देश दिया कि मिडिल ईस्ट संकट के बावजूद भारत में एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति पर असर नहीं पड़ना चाहिए. उन्होंने सभी अहम मंत्रालयों को किसी भी संभावित चुनौती के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. पीएम मोदी ने कहा है कि फिलहाल ईंधन और गैस को लेकर भारत में कोई कमी नहीं है. देश में छढक्र की पर्याप्त मात्रा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है.

भारत के पास पर्याप्त भंडार

इससे पहले केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि एलएनजी (LNG) और ऊर्जा रिजर्व को लेकर भारत की स्थिति को बहुत मजबूत और सुरक्षित बनी हुई है. उन्होंने कहा कि भारत के पास पर्याप्त भंडार और आपूर्ति है।

ईंधन की कोई कमी नहीं है. कतर के साथ अन्य देशों से LNG की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. होर्मुज जलडमरूमध्य के अलावा,

भारत अन्य रास्तों की तलाश कर रहा है.

भारत ने एतिहात के तौर पर कई कदम उठाए हैं, ताकि ज्यादा दिनों तक युद्ध चलने के बाद भी भारत को एनर्जी की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े. जिसमें गैस का उत्पादन बढ़ाना, एलपीजी बुकिंग के नियम जैसे कई कदम शामिल हैं.

Essential Commodities के तहत नया आदेश

तनाव के बीच, देश में एलपीजी गैस सप्लाई की जारी रखने के लिए एक खास कदम बढ़ाया है. सरकार ने Essential Commodities Act 1955 के तहत नेचुरल गैस सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए नए निर्देश जारी किया है. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 को नोटिफाई किया है. इसके तहत रसोई गैस की सप्लाई को प्रमुखता देना है.

इसका मतलब है कि पहले घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी, फिर कमर्शियल गैस की सप्लाई होगी. इस कारण से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में थोड़ा पैनिक सिचुएशन बन गया है.

उत्पादन बढ़ाने का आदेश

लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG की शिपमेंट मिडिल ईस्ट से बाधित होने के बाद सरकार ने तेल कंपनियों को LPG का प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया है. कई सप्लायरों ने force majeure क्लॉज भी लागू किया है. भारत के ज्यादातर LPG आयात Strait of Hormuz के रास्ते होते हैं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस निर्देश के कारण LPG के उत्पादन में 10 फीसदी की उछाल देखी गई है.

बुकिंग का नियम बदला

मंत्रालय ने बुकिंग के नियमों में बदलाव भी किया है. सरकार ने घरेलू एलपीजी सप्लाई को घरों के लिए प्राथमिकता दी है. जमाखोरी और काला बाजारी रोकने के लिए 25 दिन का एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग पीरियड (Cylinder) जैसा नियम भी लागू कर दिया है .

एक समिति बनाई गई

सरकार ने एक समिति गठत की है, जो एलपीजी से मिलने वाली गैर घरेलू सप्लाई को अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे जरूरी सेक्टर को प्राथमिकता देगी और जमाखोरी पर रोक लगाएगी. रेस्तरां, होटल और अन्य उद्योगों को LPG सप्लाई के मामलों की समीक्षा भी करेगी.

तेल और गैस आयात के नए सोर्स

सरकार ने कहा है कि भारत अब 40 से ज्यादा देशों से तेल-गैस आयात के विकल्प तैयार कर रहा है, ताकि मिडिल-ईस्ट पर निर्भरता कम हो सके और ऊर्जा की उपलब्धता बनी रहे.

बता दें, भारत के पास करीब 8 हफ्ते का तेल भंडार उपलब्ध है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है और अपनी कुल जरूरत का लगभग 85-90 फीसदी तेल विदेशों से मंगाता है. भारत के तेल आयात का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है और इसका एक महत्वपूर्ण भाग होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते से गुजरता है. जिस वजह वैश्विक स्तर पर संकट दिख रहा है.

हालांकि भारत ने जोखिम कम करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में अपनी रणनीति बदली है. देश ने रूस, अमेरिका और अफ्रीकी देशों से भी कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई है. लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर लंबे समय तक तेल संकट बना रहता है तो इससे पेट्रोल-डीजल की कीमतों, महंगाई और देश के आयात बिल पर दबाव बढ़ सकता है. हालांकि राहत की बात ये है कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है. ब्रेंट क्रूड की कीमत सोमवार की हाई 120 डॉलर प्रति बैरल से फिसलकर 90 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है.

रक्षा राज्य मंत्री सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज के तत्वावधान में भारतीय पड़ोस में बदलती परिस्थितियों पर एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे

रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 11 मार्च, 2026 को नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में सीईएनजेओडब्ल्यूएस के तत्वावधान में "भारतीय पड़ोस में बदलती परिस्थितियों" शीर्षक से एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, राजनयिक, नीति-निमार्ता और रणनीतिक विशेषज्ञ भारत के पड़ोस में उभर रहे भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच पर आएंगे। पड़ोसी देशों में हो रहे घटनाक्रमों तथा उनसे भारत के रणनीतिक और सुरक्षा वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की पड़ताल के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे।

उद्घाटन सत्र के दौरान रक्षा राज्य मंत्री द्वारा रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक सैन्य शिक्षा से संबंधित कई प्रमुख गतिविधियों का शुभारंभ किया जाएगा। इनमें सैन्य क्षेत्र के लिए सीएआईआर तथा डीआरडीओ द्वारा विकसित एआई आधारित संवाद एप्लिकेशन और भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय (आईडीयूझडीटीई) द्वारा विकसित एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम (आईओटीईपी) भी शामिल हैं।

रक्षा मंत्री ने 'रक्षा बलों के लिए विजन 2047: भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना का रोडमैप' जारी किया

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 10 मार्च, 2026 को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में 'रक्षा बलों के लिए विजन 2047: भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना का रोडमैप' जारी किया। इस विस्तृत रूपरेखा को एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय की ओर से तैयार किया गया है जिसका उद्देश्य रक्षा बलों को आधुनिक, एकीकृत और तकनीकी रूप से उन्नत सेना में परिवर्तित करना है जो 2047 तक विकसित भारत बनने की राष्ट्र की आकांक्षा को पूर्ण करने में सहयोग देने में सक्षम हो। इस दृष्टिकोण पत्र में भू-रणनीतिक, तकनीकी और सुरक्षा संबंधी बदलते परिवेश से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रक्षा बलों के अंदर आवश्यक रणनीतिक सुधारों, उनकी क्षमता में वृद्धि और संगठनात्मक परिवर्तनों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसमें सेना को एकीकृत, बहुत से संबंधित मामलों में दक्ष और कुशल बल में परिवर्तित करने की परिकल्पना की गई है जो तेजी से बदलती वैश्विक और क्षेत्रीय परिस्थितियों के बीच शत्रुओं को रोकने, संघर्ष के सभी पहलुओं से संबंधित कार्रवाई और बढ़ रहे रणनीतिक हितों की रक्षा करने में सक्षम हो।

सेना के सभी अंगों के बीच समन्वय और सहभागिता पर बल देना इस दृष्टिकोण पत्र का प्रमुख स्तंभ है

जिससे योजना, संचालन और क्षमता विकास में और अधिक तालमेल को बढ़ावा मिले। इसमें भविष्य में युद्ध की चुनौतियों के अनुकूल रक्षा बलों के निर्माण के लिए नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियों और प्रशिक्षण के आधुनिक ढांचे के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है।

इसमें प्रमुख रूप से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है जिसके अंतर्गत देश की सुरक्षा संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और समाधानों के विकास और उन्हें अपनाने को प्रोत्साहन दिया जाता है। वहीं, इसके अंतर्गत घरेलू रक्षा विनिर्माण और तकनीकी क्षमताओं को सशक्त करने से परिचालन संबंधी तैयारी में वृद्धि के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास में भी योगदान मिलने की उम्मीद है। इस दृष्टिकोण पत्र में अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक समय-सीमाओं में स्पष्ट रूप से निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षमता संबंधी लक्ष्यों के साथ सुनियोजित रूपरेखा को स्वीकार किया गया है। यह सुव्यवस्थित दृष्टिकोण विश्व स्तरीय रक्षा बल के निर्माण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं, संस्थागत सुधारों और रणनीतिक साझेदारियों के विकास में मार्गदर्शक होगा।

इस दूरदर्शी दस्तावेज में भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों की जटिलता को समझते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैन्य शक्ति को कूटनीतिक, तकनीकी और आर्थिक शक्ति के साथ जोड़ते हुए समग्र राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निरंतर सुधारों, नवाचार और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के माध्यम से भारतीय सेना देश की स्वतंत्रता की शताब्दी पूरे होने तक विश्व स्तर पर सम्मानित, तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैयार ऐसे सशस्त्र बल के रूप में स्थापित हो जो सशक्त और सामर्थ्यवान विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे।

इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, थल सेना के उप-प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

महंगाई के खिलाफ 14 मार्च को यूपी भर में कलेक्ट्रेट घेराव करेगी आम आदमी पार्टी

मोदी सरकार की गलत नीतियों ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ दी – संजय सिंह

अमेरिका के दबाव और ट्रंप के डर से चुप है मोदी सरकार, जनता को महंगाई का बोझ उठाना पड़ रहा – संजय सिंह

पहले गैस महंगी की, अब पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का खतरा, देश का आम आदमी डरा हुआ – संजय सिंह

देश की जनता से लूट बंद करे केंद्र सरकार, महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी आम आदमी पार्टी – संजय सिंह

महंगाई के खिलाफ हर जिले में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जनता की आवाज बुलंद करेगी आप – संजय सिंह

लखनऊ (जीएनएस)।

लखनऊ। 10 मार्च 2026 को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत आर्थिक और विदेश नीति के कारण देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इसका सबसे बड़ा बोझ देश के गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। हाल ही में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में की गई भारी बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। इसी बढ़ती महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा 14 मार्च को प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्ट्रेट पर प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है कि आज रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं और आम आदमी अपनी रसोई चलाने को लेकर परेशान है। उन्होंने कहा कि एक ओर देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार चुप बैठी हुई है। सरकार की विदेश नीति इतनी कमजोर हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दबाव और डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के आगे

खामोश दिखाई दे रहे हैं और इसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले गैस सिलेंडर के दामों में भारी वृद्धि की गई और अब देश के लोगों को यह डर सता रहा है कि कहीं पेट्रोल और डीजल के दामों में भी फिर से बढ़ोतरी न कर दी जाए। लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। गरीब और मध्यम वर्ग का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है, लेकिन मोदी सरकार को जनता की परेशानियों से कोई लेना-देना नहीं है संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठा रही है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश 14 मार्च को प्रदेश के सभी जिलों में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल होकर जनता की आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने पार्टी के सभी साथियों और आम जनता से अपील की कि वे अपने-अपने जिलों में आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों और लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। संजय सिंह ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाती और जनता को राहत नहीं देती तब तक आम आदमी पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा।

स्थानीय समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने सौंपा ज्ञापन, बंदर और छुट्टा पशुओं से परेशान ग्रामीण

(जीएनएस)।

बीसलपुर (पीलीभीत),

कांग्रेस कमेटी बीसलपुर के कार्यकताओं ने क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर मंगलवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से बंदरों के आतंक, छुट्टा पशुओं की समस्या तथा अन्य स्थानीय समस्याओं के समाधान की मांग की गई।

कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन समस्याओं को लेकर पार्टी की ओर से पहले भी प्रशासन को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस

कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के चलते एक बार फिर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए दोबारा ज्ञापन सौंपा गया है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि क्षेत्र में बंदरों और छुट्टा जानवरों के कारण किसानों और आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में फसलों को नुकसान हो रहा है और ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान कराने की मांग की।

इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप मौर्य, जिला सचिव राजू मिश्रा, जिला सचिव देवदत्त गंगवार, ओबीसी जिला अध्यक्ष भगवतसरन गंगवार, ब्लॉक उपाध्यक्ष विजय बहादुर, सुरेन्द्र कुमार, विनोद कुमार, प्रदीप कुमार, अमन अंसारी, सुखलाल, भगवान सिंह, कालीचरण शर्मा, रामसिंह, मेवाराम, रीतराम, अवधेश पाल, भारत सिंह, संजीव, सूरजपाल सहित कई कार्यकर्ता और ग्रामवासी मौजूद रहे।

गोयल कॉलोनी में 16-17 मार्च को मतुआ मेला: 215 वें जन्मोत्सव पर होगा महावारुणी स्नान

(जीएनएस)।

पीलीभीत,गोयल कॉलोनी, रिछोला स्थित श्री श्री शांति हरि पंचानन गोसाई सेवा आश्रम में 16 और 17 मार्च को दो दिवसीय मतुआ मेला आयोजित होगा। यह श्री श्री हरिचाँद ठाकुर जी के 215वें जन्मोत्सव पर हो रहा है, जिसमें महावारुणी स्नान और हरि नाम संकीर्तन मुख्य आकर्षण रहेंगे।

कार्यक्रम 16 मार्च को सुबह 8 बजे श्री हरि पूजा से शुरू होगा। शाम 7 बजे से कोलकाता के मतुआ शिल्पी रातभर हरि नाम संकीर्तन करेंगे। अगले दिन 17 मार्च को सुबह 10 बजे मतुआ धर्म महासम्मेलन होगा।

दोपहर 12 बजे मधु कृष्ण त्रयोदशी मुहूर्त में हजारों श्रद्धालु मनोकामना सागर में महावारुणी स्नान करेंगे, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। मतुआ धर्म में यह स्नान अत्यंत पवित्र माना जाता है।

ऑल इंडिया मतुआ महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जय किशन मंडल ने बताया कि पीलीभीत के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों से करीब 5 हजार भक्त पहुंचेंगे, जिनमें बड़ी संख्या महिलाएं शामिल होंगी। तैयारियां जोरों पर हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।

मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद होंगे। विशिष्ट अतिथियों में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान, बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद, गन्ना एवं चीनी मिलें राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, नए अध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य व उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा शामिल हैं। ये सभी 17 मार्च को सुबह 10 बजे महासम्मेलन में भाग लेंगे।

पीलीभीत में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर: एक युवक की मौत, साला गंभीर रूप से घायल; ड्राइवर फरार

(जीएनएस)।

पीलीभीत,बरेलीहाईवे पर सोमवार शाम एक तेज रफ्तार गन्ने से लदे ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। यह हादसा देवहा नदी के पुल के पास हुआ। इस दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

यह घटना थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत शाम करीब 6:00 बजे हुई। मृतक की पहचान थाना न्यूरिया क्षेत्र के ग्राम मेथी निवासी 36 वर्षीय हर प्रसाद पुत्र रामस्वरूप के रूप में हुई है। हादसे के समय हर प्रसाद अपने साले प्रेमपाल (निवासी ग्राम आमदार, थाना

बरखेड़ा) के साथ उसके घर जा रहा था।

जैसे ही उनकी बाइक देवहा पुल के पास पहुंची, गन्ने से लदे ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि हर प्रसाद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसका फायदा उठाकर ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।

सूचना मिलते ही थाना सुनगढ़ी पुलिस मौके पर पहुंची। प्रभारी निरीक्षक नरेश त्यागी ने बताया कि दुर्घटना करने वाले ट्रक को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने घायल प्रेमपाल को तत्काल एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया, जहाँ उसका उपचार जारी है। मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है।

इसी बीच, लालपुर में गजरौला थाने के समीप एक अन्य सड़क दुर्घटना में रोडवेज बस ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में गजरौला निवासी बाइक सवार अशोक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर रोडवेज बस को कब्जे में ले लिया है और घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है।

पीलीभीत के करेली क्षेत्र में दबंगों का बुजुर्ग पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला, गहरी चोटें लगीं; थाना करेली में केस दर्ज

(जीएनएस)।

पीलीभीत: जिले के करेली थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक बुजुर्ग पर लाठी-डंडों से क्रूरता से हमला बोल दिया। बुजुर्ग के शरीर पर गहरी चोटें आने से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है।

जानकारी के अनुसार, करेली थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले बुजुर्ग (उम्र करीब 65 वर्ष) अपने खेत पर काम कर रहे थे।

तभी कुछ दबंगों ने उन पर अचानक लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमलावरों ने बुजुर्ग को जमीन पर गिरा कर उनकी जमकर पिटाई की, जिससे उनके सिर, हाथ-पैरों पर गंभीर चोटें आ गईं। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीणों को देख कर हमलाव को भाग गए

घायल बुजुर्ग को परिजनों ने तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे।

अज्ञात वाहन ने मारी बाइक को टक्कर महिला की मौके पर मौत

(जीएनएस)।

उन्नाव: मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे नानामऊ गंगा पुल के पास एक सड़क हादसे में 45 वर्षीय सुनीता यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वह अपने बेटे आदित्य कुमार के साथ बाइक से बिल्हौर से अपने गांव सबलीखेड़ा लौट रही थीं। इस दुर्घटना में उनका बेटा आदित्य कुमार सुरक्षित बच गया।

बताया गया है कि सुनीता अपनी बेटी शशि के यहां बच्चा होने के बाद उसका हालचाल जानने बिल्हौर स्थित ससुराल गई थीं। लौटते समय सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण

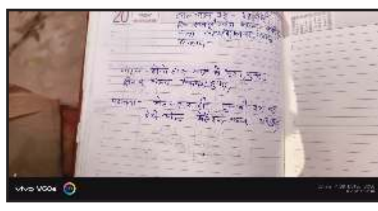

थी कि सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

मृतका सुनीता, जो सबलीखेड़ा गांव की निवासी थीं, अपने पति सुघर लाल यादव के साथ छह बच्चों की मां थीं। उनके तीन बेटे सत्यकुमार, सौरभ कुमार और आदित्य कुमार हैं, जबकि तीन बेटियां शालिनी, शशि और सोनम हैं। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

बांगरमऊ कोतवाली प्रभारी अखिलेश चंद्र पांडेय ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।

महाराजपुर गांव में छज्जा गिरने से व्यक्ति की मौत, मिस्त्री की लापरवाही ने मचाया हड़कंप

(जीएनएस)।

पीलीभीत,कलीनगर तहसील क्षेत्र के महाराजपुर गांव में मिस्त्री की लापरवाही से एक दर्दनाक हादसा हो गया। निमार्णाधीन छज्जा अचानक गिर पड़ा, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना का विवरण

घटना करीब 9 बजे की बताई जा रही है, जब महाराजपुर गांव में एक मकान के निर्माण के दौरान छज्जा भरभरा कर गिर गया। मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आसपास हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और ग्रामीणों को सूचना दी।

मिस्त्री की लापरवाही मुख्य कारण

प्रारंभिक जांच में मिस्त्री की लापरवाही सामने आ रही है। घटनास्थल पर मजदूरों के बिना उचित सुरक्षा उपायों के काम करने की बात कही जा रही है। खराब सामग्री या

गलत निर्माण तकनीक से यह हादसा हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया।

प्रशासनिक कार्रवाई

पुलिस और तहसील प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों को सांत्वना दी गई है। जिम्मेदार मिस्त्री और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। कलीनगर तहसीलदार ने जांच के आदेश दिए हैं।

पीलीभीत कोतवाली पुलिस की सजगता से पॉक्सो एक्ट के आरोपी कपिल देवल को 20 वर्ष की सजा, 71 हजार जुमार्ना।

(जीएनएस)।

पीलीभीत। पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के कुशल निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस ने गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की पैरवी से माननीय न्यायालय से एक गंभीर अपराधी को कड़ी सजा दिलाई है। मा0 न्यायालय ए एस जे /पॉक्सो प्रथम/गैंगस्टर एक्ट, पीलीभीत ने धारा 354क, 354ख, 323, 506 आई पी सी एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के अभियोग में अभियुक्त कपिल देवल पुत्र सुभाष देवल निवासी मोहल्ला खकरा पटवा वाली गली, थाना कोतवाली, जनपद पीलीभीत को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 71,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है ।यह मामला 08 फरवरी 2021 को दर्ज मुकदमा संख्या 38/2021 से जुड़ा है, जिसमें धारा 354क, 354ख, 376 क, ख, 323, 506 क्ढउ एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। गहन विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर 21 फरवरी 2021 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत पैरवीकार की प्रभावी पैरवी से विचारण पूरा हुआ और आज 10 मार्च 2026 को अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया।इस सजा से पीलीभीत पुलिस का अपराधियों पर अंकुश लगाने का संकल्प और मजबूत हुआ है, जो महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है।

'न्यूक्लियर पावर और एआई भारत को $30 ट्रिलियन की इकॉनमी बना सकते हैं': कुशाग्र बजाज

बजाज समूह के चेयरमैन और उनकी बेटी ने जय हिंद कॉलेज के फैमिली मैनेज्ड बिजनेस हब द्वारा आयोजित "मेगा नेटवर्किंग मीट- 2026" में युवा एंटरप्रेन्योर्स को दिये सफलता के मंत्र

मुंबई, 10 मार्च। देश के प्रमुख औद्योगिक समूह बजाज ग्रुप के चेयरमैन कुशाग्र बजाज ने कहा कि न्यूक्लियर पावर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत की दूरगामी इकॉनमी ग्रोथ को बढ़ाने वाली दो सबसे जरूरी इंडस्ट्रीज के तौर पर उभर सकती हैं, जिनसे आने वाले दशकों में देश को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी से $30 ट्रिलियन की इकॉनमी तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है।

श्री बजाज ने यह बात जय हिंद कॉलेज के फैमिली मैनेज्ड बिजनेस हब द्वारा आयोजित "मेगा नेटवर्किंग मीट- 2026" में बोलते हुए कही, जहाँ उन्होंने अपनी बेटी और बजाज समूह की पहली महिला उच्च अधिकारी सुश्री आनंदमयी बजाज के साथ स्टूडेंट्स, फैकल्टी और एल्युमनाई एंटरप्रेन्योर्स से बातचीत की और उन्हें अपने कैरियर में सफलता के मंत्र दिये। श्री बजाज ने कहा कि न्यूक्लियर पावर और आर्टिफिशियल

मुंबई के जय हिंद कॉलेज में आयोजित इवेंट में मुख्य अतिथि तथा बजाज ग्रुप के चेयरमैन कुशाग्र बजाज दीप प्रज्वलित करते हुए तथा दूसरे चित्र में उनकी बेटी सुश्री आनंदमयी बजाज के साथ बातचीत करते हुए। तीसरे चित्र में जय हिंद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ विजय दाभोलकर के हाथों स्मृति चिन्ह प्राप्त करते हुए श्रीमती वासवदत्ता बजाज।

इंटेलिजेंस भारत के आर्थिक भविष्य को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभायेंगे। उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर पावर बिजनेस में आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अकयुवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका है क्योंकि इसमें प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और एनर्जी सिक्योरिटी को काफी तेजी से बढ़ाने की क्षमता है, जिसके फलस्वरूप भारत $30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पीढ़ियों तक फैमिली एंटरप्राइज को बनाए रखने में मूल्यों और अनुशासन के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कंसिस्टेंसी, कड़ी मेहनत, पढ़ना और गहराई से सोचने की क्षमता फैमिली बिजनेस को ज़िम्मेदारी से बनाए रखने और उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिजनेस परिवारों को अगली पीढ़ी को मजबूत अनुशासन और ज़िम्मेदारी की भावना के साथ बड़ा करना चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि एक एंटरप्राइज बनाने और उसे बनाये रखने के लिए क्या करना पड़ता है ? लीडरशिप और सीखने पर अपना नजरिया शेयर करते हुए, बजाज ग्रुप की पॉंचवीं पीढ़ी की युवा लीडर, सुश्री आनंदमयी बजाज ने स्ट्रेटेजिक सोच को आकार देने में ग्लोबल एक्सपोजर और लगातार सीखने की वैल्यू के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने के फलस्वरूप दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। उन्होंने कहा कि विदेश में पढ़ाई करने से मेरा नजरिया बड़ा हुआ और मुझे अलग-अलग आइडिया और अनुभवों के लिए ज्यादा खुला होने में मदद मिली। उन्होंने फैमिली बिजनेस को प्रोफेशनल बनाने के महत्व पर भी जोर दिया ताकि अगली पीढ़ी अनुभवी इंडस्ट्री लीडर्स और प्रोफेशनल्स से सीख सके। उन्होंने बताया कि फैमिली बिजनेस को प्रोफेशनल बनाने से ऑर्गनाइजेशन के अंदर अनुभवी लीडर्स और एक्सपर्ट्स से सीखने का उल्लेखनीय मौका मिलता है। उन नजरियों के लिए खुला रहना और जमीनी स्तर पर सीखना, सोच-समझकर स्ट्रेटेजिक फैसले लेने और जरूरी समझ विकसित करने के लिए नितांत आवश्यक है। इस इवेंट के ऑडियंस में मिसेज वासवदत्ता बजाज भी मौजूद थीं, जो अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व में बजाज परिवार की फैमिली बॉन्डिंग को दशार्ती हैं। उनकी मौजूदगी ने सच में यह दिखाया कि किसी भी परिवार में एक महिला अपनी विविध भूमिकाओं जैसे पत्नी, माँ और सपोर्ट सिस्टम होने के लिए कितनी जरूरी है ? इस इवेंट की शाम स्पीकर्स, स्टूडेंट्स और एल्युमनाई फाउंडर्स के बीच मजेदार बातचीत के साथ खत्म हुई, जिसमें भारत के एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को बनाने में फैमिली बिजनेस, स्टार्ट-अप्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन्स के बीच कोलेबोरेशन की बढ़ती अहमियत पर जोर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि दूरदर्शी इंडस्ट्रियलिस्ट श्री जमनालाल बजाज द्वारा शुरू किया गया बजाज ग्रुप भारत के सबसे जाने-माने बिजनेस हाउसों में से एक है, जिसकी दिलचस्पी चीनी, एनर्जी, इथेनॉल और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में है। एंटरप्रेन्योरशिप, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस और नेशन-बिल्डिंग की विरासत से गाइड होकर, यह ग्रुप अपनी शुरूआती वैल्यूज पर कायम रहते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है।

पीलीभीत के दोहा पुल पर भयंकर हादसा: गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, चालक गंभीर घायल

(जीएनएस)।

पीलीभीत। जिले के दोहा पुल पर मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आ गई एक बाइक, जिसके चालक को गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचना दी, और घायल को पीलीभीत जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।

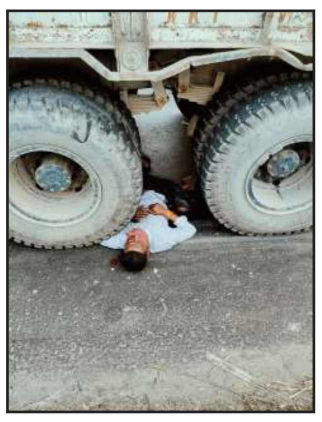

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार से पुल पर चढ़ रही थी जब बाइक सवार सामने आ गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सड़क पर लेट गया और ट्रॉली उसके नीचे से गुजरते-गुजरते बच गया। हादसे के बाद पुल पर भारी जाम लग गया, जिसे पुलिस ने करीब आधे घंटे में साफ किया। पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है, जबकि वाहन को सीज कर लिया गया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने पुल पर स्पीड ब्रेकर लगाने और ट्रैक्टरों की लोडिंग चेक करने की मांग उठाई है, क्योंकि यह क्षेत्र गन्ना परिवहन का मुख्य रूट है। जिला प्रशासन ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

पश्चिम एशिया में बवाल के कारण गैस आपूर्ति प्राभावित

इजरायल–अमेरिका और ईंरान के बीच संघर्ष के दुष्परिणाम भारत को भी भुगतने की नौबत आ ही गईं। पमि एशिया में मची तबाही का परिणाम यह हुआ कि ईंरान ने हार्मूज जलडमरूमध्य को बाधित कर दिया जिसके कारण भारत की वुल एलपीजी गैस की एक तिहाईं की आपूर्ति संकटग्रास्त हो गईं। अब भारत के लिए आवश्यक हो गया है कि वह एलपीजी के लिए प्राथमिकता का निर्धारण करे। ऐसी हालत में होटल कारोबारी वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कमी से जूझने पर मजबूर होंगे। लेकिन सरकार ने इस संकट से उबरने के लिए प्रायास शुरू कर दिए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना जारी करके गैर–प्राथमिकता क्षेत्रों से गैस मोड़कर प्रामुख उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

दरअसल सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित प्रावृतिक गैस के आबंटन के प्राथमिकता सूची में संशोधन कर दिया है और एलपीजी उत्पादन को सीएनजी और पाइप वाली (खाना पकाने की) गैस के साथ शीर्ष पर रखा है।

इससे बाजार मूल्य पर वाणिज्यिक एलपीजी का उपयोग करने वाले होटल और रेस्तरां के लिए आपूर्ति में भारी कमी होना स्वाभाविक है। सच तो यह है कि भारत अपनी 19.1 करोड़ मानक घनमीटर प्रातिदिन गैस खपत का लगभग आधा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। पश्चिम एशिया में बवाल के कारण ईंरान द्वारा बाधित गैस आपूर्ति लगभग 6 करोड़ मानक घनमीटर प्रातिदिन की गैस आपूर्ति प्राभावित हुईं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है कि वह जनसामान्य को इस संकट से राहत दिलाए। वास्तविकता तो यह है कि ईंरान इस वक्त पूरी दुनिया को इस बात का एहसास कराना चाहता है कि उसका महत्व क्या है? इसलिए न सिर्प उसने अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह करने का पैसला किया बल्कि उन देशों को भी इस युद्ध के विभीषिका के दुष्परिणामों का एहसास कराना चाहता है जो या तो अमेरिका और इजरायल के साथ खड़े दिख रहे हैं अथवा तटस्थ हैं। बहरहाल भारत के लिए यह तो जरूरी है कि वह अपनी जनता को राहत देने के लिए हर संभव प्रायास करे किन्तु परिस्थितियों से प्राभावित होकर जल्दबाजी में किसी भी पक्ष के साथ खड़ा होकर अपनी कमजोरी साबित करने का पैसला भी नहीं कर सकता। अमेरिका ने यदि ईंरान और इजरायल के फटे में टांग अड़ाईं है तो अब उसे ही तय करना है कि वह कितनी मजबूती से अपने पैर अड़ाए रखेगा। इजरायल के लिए तो ईंरान का परमाणु कार्यव्रम और बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा अस्तित्व के लिए चुनौती बन चुका है। किन्तु सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत ईंरान के साथ नैतिक रूप से खड़ा भी हो जाए तो क्या उसकी मुसीबतें कम हो जाएंगी? अपना मानना है कि बिल्वुल नहीं। इससे भारत की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। भारत ने जिस तरह निरपेक्ष सव्रियता की नीति अपनाईं है, वही सही है। मतलब यह कि युद्ध में वूदे बिना बारूदी आग के खिलाफ माहौल बनाना। ईंरान की मौजूदा सरकार और सेना जो भी पैसला ले रही है वह उनके लिए जीवन–मरण का सवाल बन चुकी है। अमेरिका समझता था कि वुछ सैन्य अधिकारियों, परमाणु विशेषज्ञों के साथ सुप्रीम लीडर के खात्मे के बाद ईंरान पस्त हो जाएगा। किन्तु उसका यह अनुमान गलत साबित हुआ। ईंरान को रूस सैटेलाइट से अमेरिकी ठिकानों की जानकारी दे रहा है और ईंरान की सेना निशाना लगा रही है।

भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाकर रहेंगे- केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा भारत- केन्द्रीय कृषि मंत्री

पश्चिम बंगाल में केंद्र की योजनाएं रोकी, किसानों को नुकसान पहुंचाया; जनता राज्य सरकार को माफ नहीं करेगी- केंद्रीय कृषि मंत्री

प्राकृतिक खेती से उत्पादन घटता नहीं, बढ़ता है- श्री शिवराज सिंह चौहान

(जीएनएस)। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में केन्द्र सरकार की योजनाओं को वहां की सरकार ठीक ढंग से लागू नहीं कर रही है।

उन्होंने कहा कि इससे राज्य के गरीब किसान केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। इसके साथ ही श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देशभर में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है।

ह्लरिकॉर्ड उत्पादन, भरे भंडार; दुनिया वाह–वाह कर रही हैह्व

कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर लगभग 357 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है जिससे भारत की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय दोनों मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि भारत ने करीब 150 मिलियन टन से अधिक चावल उत्पादन के साथ चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है, जबकि गेहूं, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली जैसी फसलों में भी रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज हुआ है। श्री चौहान के अनुसार, पहले भारत को पीएल–480 के तहत आयातित गेहूं पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज हालात यह हैं कि देश के गोदाम गेहूँ और चावल से भरे पड़े हैं और सरकार को चिंता इस बात की है कि ह्लरखे कहाँह्व, जबकि दुनिया भारत के किसानों और नीतियों की सराहना कर रही है।

प्राकृतिक खेती, दालें, फल–सब्जियाँः केंद्र की पहल, विपक्ष की चुप्पी

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फलों और सब्जियों के साथ–साथ दालों के उत्पादन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी करवाई है जिससे कुल उर्वरक उपयोग और लागत में कमी के साथ पौष्टिक आहार की उपलब्धता बढ़ी है। उन्होंने बताया कि दालों का उत्पादन लगभग 19 मिलियन टन से बढ़कर 25झ26 मिलियन टन के आसपास पहुंच गया है और बागवानी उत्पादन भी 369 मिलियन टन से अधिक के स्तर पर पहुंच चुका है जो किसानों के लिए अतिरिक्त आय का बड़ा स्रोत बना है।

प्राकृतिक खेती मिशन के तहत गंगा जैसी नदियों के किनारे के विस्तृत क्षेत्रों में रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा देने, लाखों किसानों को जागरूक करने और प्रति एकड़ प्रोत्साहन की व्यवस्था करने की जानकारी देते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर प्राकृतिक खेती सही तरीके से की जाए तो उत्पादन घटता नहीं, कई मामलों में बढ़ता है, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की उदासीनता देश के लिए चिंता का विषय है।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के गरीब किसान केंद्र की कई महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत को दुनिया का ह्लफूड बास्केटह्व बनाना और ह्लवसुधैव कुटुंबकमह्व की भावना के साथ वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान देना है।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछली सरकारों ने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध और असंतुलित उपयोग से पैदा हो रही गंभीर समस्याओं पर

कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, जबकि इससे एक ओर मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता लगातार खराब हुई, दूसरी ओर इंसानों में कई तरह की बीमारियाँ बढ़ीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकारें न तो मिट्टी के स्वास्थ्य की चिंता कर पाईं, न ही किसानों और उपभोक्ताओं को शुद्ध और पोषक आहार दिलाने की दिशा में कोई ठोस पहल कर सकीं। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनौती को समय रहते समझा और स्पष्ट संदेश दिया कि यह धरती केवल हमारी पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और उपजाऊ रहनी चाहिए।

प्राकृतिक खेती मिशनः ह्लउत्पादन घटता नहीं, बढ़ता हैह्व

श्री शिवराज सिंह ने प्राकृतिक खेती मिशन और जैविक खेती मिशन का ज़िक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं के जरिए सरकार मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने, भूमि को रसायनमुक्त बनाने और किसानों की लागत घटाकर उनकी आय बढ़ाने पर फोकस कर रही है। उन्होंने बताया कि गंगा जैसी नदियों के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर तक के क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि पानी, जमीन और इंसानझ तीनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि देशभर में 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित किया गया है और लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में क्लस्टर बनाकर रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक मुक्त खेती शुरू हो चुकी है।

किसान को प्रोत्साहन, स्थानीय संसाधनों से खेती का मॉडल

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्राकृतिक खेती में किसानों को प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जा रही है ताकि वे रासायनिक खाद और महंगे कीटनाशकों की जगह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों पर आधारित पारंपरिक भारतीय पद्धतियां अपनाएं। उन्होंने समझाया कि इस मॉडल में खेत और गांव के आसपास मिलने वाली वनस्पतियों, देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से तैयार घनजीवामृत, बीजामृत और नीमास्त्र जैसी देसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। साथ ही इंटरक्रॉपिंग के जरिए एक ही खेत में अलग–अलग फसलें ली जाती हैं। श्री चौहान ने दावा किया कि सही तरीके से प्राकृतिक खेती अपनाने पर उत्पादन घटने की आशंका निराधार है, बल्कि देश के कई हिस्सों के प्रयोगों में यह साबित हुआ है कि किसानों की पैदावार पहले से ज्यादा हुई है और उत्पाद की गुणवत्ता भी बेहतर मिली है।

ह्लहरित क्रांति से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है भारतह्व

श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आज भारत का खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति के शुरूआती दौर की तुलना में कई गुना अधिक हो चुका है और अब वृद्धि की रफ्तार भी पहले से तेज है। उन्होंने कहा कि 2014झ15 के मुकाबले खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 40झ42 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है, दलहन, तिलहन, बागवानी और दुग्ध उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भी लगातार नए कीर्तिमान बन रहे हैं, जिसका सीधा फायदा किसानों की आय और देश की खाद्य सुरक्षा झ दोनों को मिल रहा है। मंत्री श्री शिवराज सिंह ने यह भी रेखांकित किया कि ह्लसेल्फ–रिलायंस इन पल्सेज मिशनह्व और बागवानी के लिए की गई पहलों ने दालों और फल–सब्जियों के उत्पादन को नए स्तर पर पहुँचाया है, जिससे पोषण सुरक्षा को मजबूत आधार मिला है।

ह्लभारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाकर रहेंगेह्व

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन है कि भारत केवल अपने नागरिकों की खाद्य सुरक्षा तक सीमित न रहे, बल्कि विश्व बंधु की भावना के साथ दुनिया की जरूरतों को भी पूरा करने वाला ह्लफूड बास्केट ऑफ द वर्ल्डह्व बने। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में रिकॉर्ड उत्पादन, मजबूत भंडारण क्षमता और निर्यात की संभावनाओं ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित किया है और आने वाले समय में यह भूमिका और मजबूत होगी।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी

(जीएनएस)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज जल शक्ति मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन को बुनियादी ढांचे के निर्माण से पुनर्गठित करने और इसे सेवा वितरण की ओर मोड़ने की बात कही गई है। इसकी पेयजल व्यवस्था और स्थायी ग्रामीण पाइपलाइन से पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए संस्थागत इकोसिस्टम द्वारा सहायता की जाएगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जेजेएम के पुनर्गठन के लिए, कुल परिव्यय को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है, जिसमें कुल केंद्रीय सहायता 3.59 लाख करोड़ रुपये है। यह 2019–20 में स्वीकृत 2.08 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, यानी 1.51 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त केंद्रीय हिस्सा है।

इस उद्देश्य से, एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा, जिसे ह्लसुजलम भारतह्व कहा जाएगा, स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव/सेवा क्षेत्र आईडी आवंटित की जाएगी, जो स्रोत से नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्रण करेगी। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए , ह्लजल अर्पणह्व के माध्यम से योजनाओं के शुभारंभ और औपचारिक हस्तांतरण में ग्राम पंचायतों और पशु एवं जल आपूर्ति समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

ग्राम पंचायत राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त संचालन एवं रखरखाव तंत्र स्थापित किए जाने की पुष्टि होने पर ही कार्यों के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जारी करेगी और स्वयं को ह्लहर घर जलह्व घोषित करेगी। सामुदायिक स्वामित्व और भागीदारी को परिचालन दक्षता और जल स्रोत की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए, यह कार्यक्रम ह्लजल उत्सवह्व को एक वार्षिक, समुदाय–नेतृत्व वाले रखरखाव एवं समीक्षा कार्यक्रम के रूप में बढ़ावा देगा, जिसमें स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों को शामिल करते हुए पेयजल की सुरक्षा के लिए सामूहिक जिम्मेदारी को सुदृढ़ किया जाएगा।

वर्ष 2019 में नल–जल कनेक्शन वाले 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों की आधारभूत स्थिति से, अब तक जल जीवन मिशन (जेजेएम) योजना के तहत 12.56 करोड़ से अधिक अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल–जल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्तमान में, देश में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चिन्हित 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, लगभग 15.80 करोड़ (81.61 प्रतिशत) परिवारों के पास नल–जल कनेक्शन उपलब्ध हैं।

वास्तविक उपलब्धियों के अतिरिक्त, जेजेएम के प्रभावों का आकलन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा किया गया है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, जेजेएम ने 9 करोड़ महिलाओं को पानी ढोने के काम से मुक्त किया है, जिससे वे अन्य आर्थिक कार्यकलापों में अधिक भागीदारी कर पा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अनुमान लगाया है कि जेजेएम से महिलाओं के श्रमसाध्य कार्य में प्रतिदिन 5.5 करोड़ घंटे की बचत हुई है, डायरिया से होने वाली 4 लाख मौतों को रोका जा सका है और 14 मिलियन विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (डीएएलवाई) की बचत हुई है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर माइकल क्रेमर ने पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 30 प्रतिशत की संभावित कमी का अनुमान लगाया है, जिससे प्रतिवर्ष 1,36,000 बच्चों की जान बचाई जा सकती है; आईआईएम बैंगलोर और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने जेजेएम के माध्यम से 59.9 लाख प्रत्यक्ष और 2.2 करोड़ अप्रत्यक्ष व्यक्ति–वर्ष के संभावित रोजगार सृजन का अनुमान लगाया है, जिससे ग्रामीण आजीविका मजबूत हुई है। महिलाएं और बालिकाएं इस पहल की प्रमुख लाभार्थी बनकर उभरी हैं, जिन्हें श्रमसाध्य कार्य में कमी, बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता, बढ़ी हुई गरिमा और शिक्षा एवं आजीविका कार्यकलापों के अधिक अवसरों के रूप में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए हैं।

जेजेएम 2.0 देश भर के सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को दिसंबर 2028 तक नल–जल कनेक्शन उपलब्ध कराकर सभी ग्राम पंचायतों को 'हर घर जल' के प्रमाणन में सहयोग देगा। साथ ही, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अलग–अलग समझौता ज्ञापनों के माध्यम से समय–सीमा का पालन, योजना की निरंतरता और नागरिक–केंद्रित जल सेवाओं का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। जेजेएम 2.0 संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से अवसंरचना–केंद्रित दृष्टिकोण से नागरिक–केंद्रित उपयोगिता–आधारित सेवा वितरण दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए, 247 सुनिश्चित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के साथ विकसित भारत @2047 के विजन को भी बढ़ावा देता है।

जल जीवन मिशन 2.0 के तहत, भारत सरकार के समग्र दृष्टिकोण के साथ, ग्रामीण जल आपूर्ति अवसंरचना के सतत और दीर्घकालिक संचालन एवं रखरखाव तथा योजना स्रोत के निरंतर संचालन के लिए विभिन्न विभागों के बीच रणनीतिक समन्वय की परिकल्पना भी की गई है।

कैबिनेट ने भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश के लिए दिशा-निर्देशों में बदलाव को मंजूरी दी

कैबिनेट ने पीएन3 के तहत मंजूरी की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए एक निश्चित समय-सीमा प्रदान करने हेतु एफडीआई नीति में बदलावों को मंजूरी दी

एफडीआई नीति में इन संशोधनों का उद्देश्य स्टार्टअप्स और डीप टेक के लिए वैश्विक फंडों से अधिक एफडीआई निवेश को आकर्षित करना और कारोबार में सुगमता की कार्य योजना को आगे बढ़ाना है

60 दिन में त्वरित निर्णय से कंपनियों को भारत में विनिर्माण का विस्तार करने के लिए सहयोग स्थापित करने में मदद मिलेगी

कंपनियों को नई तकनीकों तक पहुँचने के लिए संयुक्त उद्यम बनाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जुड़ने में मदद करने के लिए 60 दिन की निर्णय/मंजूरी समय-सीमा तय

जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश के लिए एफडीआई नीति में कैबिनेट द्वारा मंजूर बदलावों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, पूंजीगत वस्तुओं और सोलर सेल्स के विनिर्माण में मदद मिलेगी

(जीएनएस)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों (एलबीसी) से होने वाले निवेश के दिशानिर्देशों में बदलाव को मंजूरी दे दी।

मौजूदा नीति की समीक्षा की गई है और इसमें निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

क. 'बेनेफिशियल ओनर' (वास्तविक स्वामी–बीओ) की परिभाषा और उसके निर्धारण के मानदंड शामिल करना।

यह संशोधन वास्तविक स्वामित्व की एक ऐसी परिभाषा और निर्धारण के मानदंड प्रदान करता है जो निवेश समुदाय द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, और जो धन शोधन निवारण नियम, 2003 के अंतर्गत आते हैं।

वास्तविक स्वामित्व की जांच निवेशक इकाई के स्तर पर लागू की जाएगी।

जिन निवेशकों में जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों की गैर–नियंत्रक बेनेफिशियल ओनरशिप 10 प्रतिशत तक है, उन्हें स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि संबंधित क्षेत्रीय सीमा, प्रवेश मार्ग और अन्य लागू शर्तों का पालन किया जाए। ऐसे निवेशों के मामले में निवेश प्राप्त करने वाली कंपनी को संबंधित जानकारी/विवरण उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) को रिपोर्ट करना होगा।

ख. विशिष्ट क्षेत्रों में निवेश के लिए त्वरित स्वीकृतिझ

इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, पॉलीसिलिकॉन तथा इन्गट–वेफर के निर्माण से संबंधित निर्दिष्ट क्षेत्रों/गतिविधियों में एलबीसी निवेश के प्रस्तावों को 60 दिनों के भीतर संसाधित कर निर्णय लिया जाएगा।

कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सीओएस आवश्यकतानुसार निर्दिष्ट क्षेत्रों की सूची में संशोधन भी कर सकती है।

इन मामलों में निवेश प्राप्त करने वाली इकाई में बहुसंख्यक शेयरधारिता और नियंत्रण हमेशा भारतीय निवासी नागरिकों और/या भारतीय निवासी संस्था के पास होगा, जिसका स्वामित्व और नियंत्रण भारतीय निवासी नागरिक के हाथ में होगा।

पृष्ठभूमि

कोविड–19 महामारी के कारण भारतीय कंपनियों के मौकापरस्त नियंत्रण/अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार ने 17.04.2020 के प्रेस नोट 3 (2020) (पीएन3) के माध्यम से मौजूदा एफडीआई नीति में संशोधन किया था। पीएन3 के अनुसार, भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देश की कोई भी इकाई, या जहाँ भारत में होने वाले निवेश का वास्तविक मालिक ऐसे किसी देश में स्थित हो या उसका नागरिक हो, वह केवल सरकारी मार्ग के तहत ही निवेश कर सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत में किसी इकाई में मौजूद या भविष्य के किसी भी एफडीआई के स्वामित्व के हस्तांतरण के मामले में, यदि इससे वास्तविक स्वामित्व उपरोक्त अधिकार क्षेत्र के दायरे में आता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मिले-जुले वार्षिकी आधार पर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लभगढ़-सोहना उपमार्ग से जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक नए सड़क निर्माण के संशोधित परिव्यय की मंजूरी दी

(जीएनएस)। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हाइब्रिड वार्षिकी आधार पर दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली–फरीदाबाद–बल्लभगढ़–सोहना उपमार्ग से जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक नए सड़क निर्माण के लिए 3630.77 करोड़ रुपये के संशोधित परिव्यय को स्वीकृति दे दी।

31.42 किलोमीटर लंबा यह गलियारा दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक सीधी और उच्च गति का संपर्क मार्ग होगा जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आर्थिक विकास और

प्रचालन दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।

यह गलियारा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ेगा जिससे बहुआयामी परिवहन संभव होगा। यह उच्च गलियारा संरचनात्मक सुधार के साथ ही शहरी अवसंरचना परिवर्तन, क्षेत्रीय संपर्क और राष्ट्रीय परिचालन दक्षता का महत्वपूर्ण साधन होगा। जेवर हवाई अड्डे -दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर की पूरी क्षमता के उपयोग और फरीदाबाद में सतत शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए इसका निर्माण अत्यंत आवश्यक है।

इस परियोजना का लगभग 11 किलोमीटर लंबा हिस्सा एलिवेटेड मार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा जो डीएनडी–बल्लभगढ़ बाईपास और जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच नए संपर्क मार्ग का महत्वपूर्ण खंड है और इसे दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। यह गलियारा फरीदाबाद मास्टर प्लान, 2031 के तहत घनी आबादी वाले शहरी विकास और भविष्य के बुनियादी ढांचे के विस्तार के निर्धारित क्षेत्र से होकर गुजरेगा। प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर की अतिरिक्त लागत 689.24 करोड़ रुपये है। हरियाणा सरकार ने इसमें 450 करोड़ रुपये वहन करने पर सहमति जताई है।

भारत-ईएफटीए टीईपीए समझौते के दो वर्ष पूरे हुए; व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधी सहयोग को मजबूती मिली

(जीएनएस)। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के सदस्य देशों, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे तथा स्विट्जरलैंड के बीच व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए जाने के दो वर्ष बाद, यह साझेदारी 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी रूप से बातचीत के स्तर से कार्यान्वयन की दिशा में अग्रसर हो गई है। यह समझौता भारत और उन्नत यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के एक समूह को एक ऐसे ढांचे में एक साथ लाता है जो व्यापार, निवेश, सेवाओं, प्रौद्योगिकी संबंधी सहयोग और दीर्घकालिक औद्योगिक विकास को समर्थन प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहाः ह्लपिछले कुछ वर्षों में, हमने मुक्त व्यापार समझौतों का एक रणनीतिक और उद्देश्यपूर्ण नेटवर्क बनाया है। अब हमारे 38 साझेदार देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते हैं, जो भारतीय व्यापार के इतिहास में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। इन व्यापार समझौतों की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि ये विभिन्न महाद्वीपों तक फैले हुए हैं और इनमें विभिन्न आर्थिक शक्तियों वाले देश शामिल हैं। इससे हमारे निमार्ताओं और उत्पादकों को विभिन्न बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने हेतु पर्याप्त विविधता और क्षमता मिलती है। हमारा सेवा क्षेत्र और इसके पेशेवर विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पहले ही भारत को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित वैश्विक क्षमता केन्द्रों का हब बना दिया है। इन व्यापार समझौतों ने हमारे विभिन्न साझेदार देशों में नियामकीय निश्चितता, पारस्परिक रूप से लाभकारी ढांचों और अधिक गतिशीलता के साथ उनके अवसरों को और अधिक बढ़ावा दिया है। हमारा मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों से अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है और ये व्यापार समझौते भारत व भारतीय उत्पादों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में और अधिक गहराई से समाहित करने में मदद करेंगे। इनसे भारतीय उत्पादकों और निमार्ताओं को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही हमारे लोगों की समृद्धि में भी वृद्धि होगी।ह्व

दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर, केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा, ह्लभारत–ईएफटीए टीईपीए एक दीर्घकालिक आर्थिक उद्देश्य वाला समझौता है। यह भारतीय निर्यातकों को उच्च आय वाले बाजारों तक पहुंच प्रदान करता है, 15 वर्षों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है और विशेष मशीनरी, गुणवत्तापूर्ण इनपुट एवं प्रौद्योगिकी साझेदारी तक पहुंच को बेहतर बनाता है जो भारत में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूत कर सकता है। यह उत्पादन बढ़ाने, मानकों में सुधार करने, मूल्यवर्धन को गहरा करने और भारत के 2030 के निर्यात संबंधी लक्ष्य की ओर बढ़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैह्व

लिवलॉन्ग ने लखनऊ में नई शाखा खोलकर अपनी मौजूदगी का विस्तार किया

लखनऊ, 10 मार्च 2026: भारत की अग्रणी बीमा और एकीकृत हेल्थ-टेक प्लेटफॉर्म, लिवलॉन्ग ने लखनऊ में अपनी नई शाखा शुरू करने की घोषणा की है। यह विस्तार सुलभ और हाइपरलोकल स्वास्थ्य सेवा और बीमा समाधान प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। इस नई शाखा के साथ, लिवलॉन्ग का लक्ष्य प्रमुख शहरी क्षेत्रों में अपनी ऑफलाइन उपस्थिति बढ़ाना है, ताकि ग्राहकों को उनके करीब ही स्वास्थ्य सेवाएं और बीमा विकल्प मिल सकें।

लखनऊ शाखा रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट डढऊ प्रोग्राम और रटए-केंद्रित बीमा समाधानों में विकास के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करेगी। लखनऊ के व्यस्त आवासीय क्षेत्रों में से एक में स्थित यह शाखा व्यक्तियों, कॉर्पोरेट घरानों और छोटे व्यवसायों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करेगी।

इस दौरान गौरव दुबे (संस्थापक और सीईओ, लिवलॉन्ग): ने कहा कि "लखनऊ हमारी राष्ट्रीय विस्तार यात्रा का एक प्रमुख बाजार है। इस नई शाखा के साथ, हम अपनी हाइपरलोकल उपस्थिति को मजबूत

कर रहे हैं और एकीकृत स्वास्थ्य बीमा और वेलनेस समाधानों को क्षेत्र के लोगों और व्यवसायों के लिए अधिक सुलभ बना रहे हैं।"

मोहित भारद्वाज (मुख्य वितरण अधिकारी और सेल्स हेड, लिवलॉन्ग): के अनुसार "लखनऊ शाखा उत्तर भारत में लिवलॉन्ग के वितरण और पार्टनर इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करेगी। यह पूरे क्षेत्र में हमारे एकीकृत स्वास्थ्य समाधानों की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करेगा।"

डॉ. सौम्य कुमार मिश्रा (नेशनल हेड, इंडसइंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड):ने कहा "हम लिवलॉन्ग के लखनऊ विस्तार में उनके साथ जुड़कर खुश हैं। यह साझेदारी बढ़ते बाजारों में ग्राहकों को व्यापक स्वास्थ्य बीमा समाधान और सार्थक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को दशार्ती है।"

यह नई शाखा अगले दो वर्षों में देश भर में 100 शाखाएँ खोलने की लिवलॉन्ग की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। दिल्ली, बेंगलुरु, नासिक, कोलकाता, नागपुर और अंधेरी में हाल ही में हुए लॉन्च के बाद, लखनऊ शाखा ओपीडी सेवाओं, स्वास्थ्य बीमा और वेलनेस कार्यक्रमों के लिए भारत का सबसे भरोसेमंद और सुलभ मंच बनने के लिवलॉन्ग के विजन को पुख्ता करती है।

सबसे पहले लिवलॉन्ग 365 लखनऊ शाखा का भव्य उद्घाटन मुख्य अतिथिः डॉ. सौम्य कुमार मिश्रा (नेशनल हेड, इंडसइंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) का उद्घाटन लिवलॉन्ग प्रोटेक्शन एंड वेलनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड, ऑफिस नं. 4, दूसरी मंजिल, सेंटर कोर्ट, राधा कृष्ण भवन के पीछे, 3/उ 5-पार्क रोड, लखनऊ में किया गया।

श्याम बगिया सोसाइटी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होली मिलन समारोह

लखनऊ। पुराना हैदराबाद स्थित श्याम बगिया सोसाइटी द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन बड़े उत्साह और सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में सोसाइटी के लोगों ने आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ होली के पर्व का आनंद लिया।

समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री अशोक बाजपेयी उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में कॉल्विन कॉलेज वार्ड के पार्षद श्री प्रमोद सिंह ह्यराजनह्र ने कार्यक्रम में शिरकत की। अतिथियों ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में आपसी मेलजोल और भाईचारे को मजबूत करते हैं।

कार्यक्रम के दौरान सोसाइटी के बच्चों और निवासियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिनकी सभी ने सराहना की। बच्चों के नृत्य और गीतों ने माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया।

कार्यक्रम का संचालन श्री दीपक चौधरी, सुश्री तान्या और सुश्री भाव्या ने संयुक्त रूप से किया। उनके संचालन ने पूरे कार्यक्रम को सुव्यवस्थित और रोचक बनाए रखा।

समारोह के अंत में सभी अतिथियों और सोसाइटी के लोगों के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों की भी व्यवस्था की गई, जिसका सभी ने आनंद लिया। पूरे आयोजन में उत्साह, उमंग और आपसी सौहार्द का वातावरण देखने को मिला।

लिवलोंग ने नई शाखा की ओपनिंग के साथ लखनऊ में किया अपने फुटप्रिन्ट का विस्तार

लखनऊ & भारत के अग्रणी इंश्योरेन्स एवं इंटीग्रेटेड हेल्थ-टेक प्लेटफॉर्म लिवलोंग ने लखनऊ में अपनी नई शाखा खोलने की घोषणा की है इसके साथ कंपनी ने हेल्थकेयर एवं बीमा समाधानों को सुलभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत बना लिया है। इस विस्तार के साथ लिवलोंग मुख्य शहरी क्षेत्रों में अपनी ऑफलाईन मौजूदगी को सशक्त तथा समग्र हेल्थकेयर, वैलनैस एवं बीमा सेवाओं को उपभोक्ताओं एवं साझेदारों के लिए सुलभ बनाने के प्रयास जारी रखे हुए है।

लखनऊ की यह शाखा रीटेल हेल्थ इंश्योरेन्स कॉर्पोरेट ओपीडी प्रोग्रामों और एसएमई-फोकस्ड इंश्योरेन्स समाधानों में विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हब की भूमिका निभाएगी। शहर के सबसे व्यस्त रिहायशी इलाकों में से एक में स्थित इस शाखा का उद्देश्य आम लोगों, कॉर्पोरेट्स एवं छोटे कारोबारों के लिए हेल्थकेयर सुरक्षा की बदलती जरूरतों को पूरा करना है।

इस अवसर पर लिवलोंग के संस्थापक एवं सीईओ गौरव दुबे ने कहा - लखनऊ हमारे राष्ट्रीय विस्तार

की यात्रा में एक मुख्य मार्केट है। इस नई शाखा के साथ हम अपनी स्थानीय मौजूदगी को सशक्त बना रहे हैं तथा इंटीग्रेटेड हेल्थ इंश्योरेन्स एवं वैलनैस समाधानों को क्षेत्र के आम लोगों एवं कारोबारों के लिए अधिक सुलभ बना रहे हैं।

लिवलोंग के चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर और सेल्स हैड मोहित भारद्वाज ने कहा - लखनऊ शाखा उत्तर भारत में लिवलोंग के डिस्ट्रीब्यूशन एवं पार्टनर इकोसिस्टम को सशक्त बनाएगी। यह हमें उपभोक्ताओं के साथ करीब से जोड़ेगी तथा हमारे इंटीग्रेटेड हेल्थ इंश्योरेन्स एवं वैलनैस समाधानों को अधिक सुलभ बनाने में योगदान देगी।

इंडसइंड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के नेशनल हैड डॉ सौम्या कुमार मिश्रा ने कहा & हमें खुशी है कि हमें लखनऊ में लिवलोंग की मौजूदगी बढ़ाने के लिए उनके साथ साझेदारी का मौका मिला है। यह साझेदारी व्यापक हेल्थ इंश्योरेन्स समाधानों को सुलभ बनाने और उपभोक्ताओं को बेहतर हेल्थकेयर सुरक्षा उपलब्ध कराने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को दशार्ती है।

लखनऊ शाखा के उद्घाटन के अवसर पर इंडसइंड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के नेशनल हैड डॉ सौम्या कुमार मिश्रा मौजूद रहे।

देश भर में अगले दो सालों में 100 शाखाएं खोलने की योजनाओं के तहत लिवलोंग ने यहनई शाखा खोली है। हाल ही में दिल्ली, बैंगलुरू, नासिक, कोलकाता, नागपुर और अंधेरी में लॉन्च के बाद लखनऊ की यह शाखा ओपीडी सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेन्स एवं वैलनैस प्रोग्रामों के लिए भारत के सबसे भरोसेमंद एवं सुलभ प्लेटफॉर्म बनने के लिवलोंग के विजन को मजबूत बनाती है।

वेटेरिनरी यूनिवर्सिटी का 15-वां दीक्षांत समारोह हुआ सम्पन्न : मेधावी छात्र-छात्राओं को राज्यपाल ने दीं उपाधियां

मथुरा (जीएनएस)। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान (वेटेरिनरी कॉलेज) में 15-वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेधावी छात्र-छात्राओं को पदक और उपाधियां प्रदान करके उनके बधाई दीं। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विद्यार्थियों में जोश भरते हुए कहा कि मथुरा भगवान श्रीकृष्ण की पावन लीला स्थली है, लेकिन वर्तमान में आपका समय श्रीकृष्ण की लीलाओं पर ध्यान देने का नहीं, बल्कि अपनी पढ़ाई और कैरियर पर एकाग्र होने का

है। कहा कि जब आप पूरी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई करेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इस मौके पर उन्होंने युवा चिकित्सकों से अपील करते हुए कहा कि वह देश के विकास में योगदान दें और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं दें। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ केन्द्रीय पशुपालन आयुक्त डा. नवीन बी. महेश्वरप्पा और पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने उपाधियां वितरित कीं। इस अवसर पर 69 बीवीएससी, 74 स्नातकोत्तर (एमवीएससी), 5 पीएचडी और 29 बायोटेक्नोलॉजी की उपाधियां प्रदान की गईं तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 14 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक दिए गए। स्नातकोत्तर के 4 और पीएचडी के 1 सर्वश्रेष्ठ शोध प्रबंध (थीसीस) के साथ सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इस दौरान तीन महत्वपूर्ण पुस्तकों का भी अनावरण किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंच से डीएम की पीठ थपथपाई। दीक्षांत समारोह के दौरान एक दिलचस्प वाक्या उस समय हुआ जब राज्यपाल ने मंच से ही डीएम सीपी सिंह की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सरकारी सुविधाओं पर हर जरूरतमंद का हक है। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि डीएम ने सोमवार को 112 वर्षीय एक वृद्धा को मात्र तीन दिन में पेंशन दिलाने के जो आदेश दिया, वह सराहनीय है। इसके साथ ही उन्होंने ब्रज क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और डीएम की कार्यशैली की भी प्रशंसा की।

नाली विवाद में दो पक्षों में मारपीट, युवक गंभीर घायल

कौशांबी। जनपद कोखराज थाना क्षेत्र के चक चमरूपुर गांव में नाली को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई।सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मारपीट के दौरान मानसिंह पुत्र शुगर कुमार यादव को गंभीर चोट लग गई, जिससे उनके सिर और शरीर

से काफी खून बहने लगा। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई।बताया जा रहा है कि घायल की हालत गंभीर बनी हुई है और लोगों द्वारा उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है।फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है।

60 घर, 100 टैंकर पानी और 2.5 एकड़ का सेटः 'आया शेर' के लिए द पैराडाइज मेकर्स ने बनाया ग्रैंड स्लम वर्ल्ड

'आया शेर' के लिए द पैराडाइज मेकर्स ने बनाया 2.5 एकड़ का स्लम सेट, डीटेल्स पढ़ उड़ जाएंगे होश

मुम्बई, 'आया शेर' इस साल की सबसे बड़ी हिट्स में से एक है, जिसने कई भाषाओं में मिलियंस व्यूज बटोरे हैं और इंस्टाग्राम रील्स पर इसका जलवा कायम है। इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए, मेकर्स ने एक भव्य 'स्लम एम्पायर' का सेट तैयार किया, जिसमें हीरो को स्लम के सम्राट के रूप में दिखाया गया है।

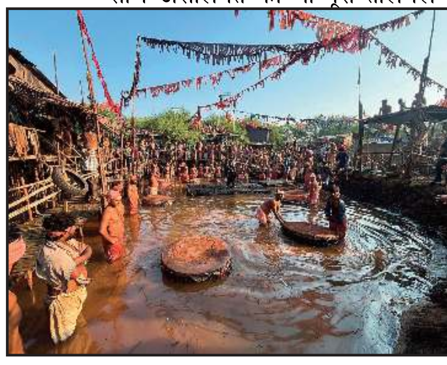

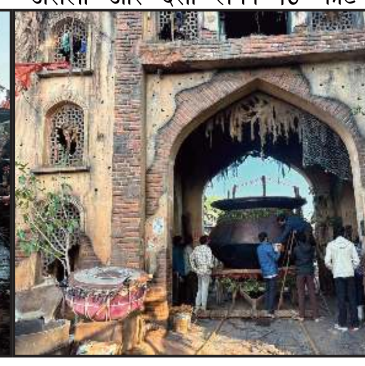

'द पैराडाइज' का टीजर जब से रिलीज हुआ है, इसे लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। ऑडियंस की तरफ से इसे बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और देखते ही देखते इसने ऑनलाइन मिलियंस में व्यूज बटोर लिए हैं। टीजर ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है और फिल्म को लेकर लोगों की क्यूरियोसिटी को दोगुना कर दिया है। इसी बढ़ते क्रेज की वजह से 'द पैराडाइज' इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन गहाल ही में रिलीज हुए फिल्म 'द पैराडाइज' के गाने 'आया शेर' ने अपनी जबरदस्त एनर्जी और कमाल के विजुअल्स से लोगों को इम्प्रेस कर दिया है। इस गाने के इतने बड़े लेवल और असली दिखने के पीछे एक बड़ी वजह फिल्म के आर्ट डिपार्टमेंट की मेहनत है, जिन्होंने बहुत ही शानदार सेट्स तैयार किए। इन सेट्स में भव्यता के साथ-साथ असलियत का भी पूरा तालमेल बिठाया गया है।

सबसे खास सेटअप्स में से एक 'हीरो हाउस' (कमान सेट) है, यह 60 फीट चौड़ा, 45 फीट ऊँचा और 25 फीट गहरा एक विशाल स्ट्रक्चर है, जिसे खास तौर पर हीरो के दमदार डिप (ग्ह्रि) वाले सीन के लिए बनाया गया था। शुरूआत में इसे 30 फीट चौड़ा बनाया गया था, लेकिन बाद में दोनों तरफ 15-15 फीट और बढ़ाकर इसकी चौड़ाई 60 फीट कर दी गई। लगभग 25 वर्कर्स ने करीब 20 दिनों तक मेहनत करके इस बड़े स्ट्रक्चर को तैयार किया, और इसे आसपास के माहौल के साथ एकदम असली दिखाने के लिए खास 'एजिंग' (पुराना दिखाने की) तकनीक का इस्तेमाल किया गया।

गाने में एक और अनोखी चीज देखने को मिली है, वो है बिरयानी के बड़े कटोरे जैसा स्ट्रक्चर। इसे तांबे (ङ्क्षस्न्न्नेा१) की फिनिश और पुराना लुक दिया गया है ताकि ये एकदम असली और देसी लगे। 10 फीट चौड़ाई, 20 फीट रेडियस और 6 फीट ऊंचाई वाले इस सेटअप को 5-7 लोगों की टीम ने सिर्फ पांच दिनों में तैयार कर दिया था।प्रोडक्शन के लेवल को और बड़ा बनाने के लिए 2.5 एकड़ में फैला 'वॉटर बॉडी विलेज सेट' तैयार किया गया था, जिसमें डमी स्ट्रक्चर्स के बजाय 60 असली घर बनाए गए थे। लगभग 50 वर्कर्स ने 30 दिनों तक मेहनत करके इस गांव को बनाया, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि इसमें एक साथ करीब 500 लोग आ सकें। पानी का सीन क्रिएट करने के लिए 100 टैंकर पानी मंगवाया गया, जिसे भरने में सात दिन लगे। साथ ही, पानी जमा करने के लिए 20 फीट गहरा एक अलग तालाब भी बनाया गया था।प्रोडक्शन ने एक बहुत बड़ा 'डंप यार्ड' सेट भी तैयार किया, जो 120 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा और 30 फीट ऊँचा था। 25 लोगों की टीम ने 30 दिनों की मेहनत से इसे बनाया, जिसका मकसद एक असली डंप यार्ड जैसा 'रस्टिक' और पुराना लुक देना था।

इन सेट्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इन्हें कुदरती माहौल को नुकसान पहुँचाए बिना बनाया गया। आर्ट डिपार्टमेंट ने बहुत सावधानी से इन स्ट्रक्चर्स को वहां की जमीन और नजारों के साथ जोड़ा। असलियत दिखाने के लिए नेचुरल टेक्सचर्स और 'एजिंग' (पुराना दिखाने की) तकनीक का जमकर इस्तेमाल किया गया।

हर सेटअप की प्लानिंग बहुत बारीकी से की गई थी ताकि काम बिना किसी रुकावट के और क्रिएटिव तरीके से पूरा हो सके। सभी जरूरी मंजूरियां लेने के बाद ही फाइनल कंस्ट्रक्शन किया गया।

इसका नतीजा 'आया शेर' गाने में दिखने वाले शानदार विजुअल्स हैं, जो दर्शकों को उस भव्य और दमदार दुनिया की झलक दिखाते हैं जिसे 'द पैराडाइज' बड़े पर्दे पर लाने का वादा करती है।

जिलाधिकारी ने गर्मी के दृष्टिगत गौशालाओं में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश

जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल की अध्यक्षता में उदयन सभागार में गोसंरक्षण के सम्बन्ध में जिलास्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई।

जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को गौशालाओं में सी.सी.टी.वी. की क्रियाशीलता एवं भूसा-चारा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने चारागाह की भूमि का प्रबन्धन व चारा उत्पादन की समीक्षा के दौरान विकास खण्ड कड़ा व कौशाम्बी में गौशालाओं के लिए चिन्हित चारागाह की भूमि पर चारे की बुआई कम पाए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए खण्ड विकास अधिकारी कड़ा एवं कौशाम्बी का वेतन रोकने के निर्देश देते हुए सभी खण्ड विकास अधिकारियों को प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी गौशालाएं, जहॉ पर वर्षा ऋतु में जल-जमाव हो जाता है, जल निकासी/वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करा लिया जाय। उन्होंने कहा कि गर्मी के दृष्टिगत गौशालाओं में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा लिया जाय।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

जिलाधिकारी ने की जिला पर्यावरण समिति एवं जिला गंगा समिति की बैठक

जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल की अध्यक्षता में उदयन सभागार में जिला पर्यावरण समिति एवं जिला गंगा समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी ने पौधारापेण अभियान-2026 के अन्तर्गत सभी अधिकारियों को गाइडलाइन के अनुसार आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत पौधारोपण कराए जाने के लिए तैयारियॉ समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभागीय वनाधिकारी से कहा कि विभागों से कार्ययोजना प्राप्त कर लिया जाय तथा नर्सरियों में फलदार पौधों का प्रतिशत बढ़ाया जाय। पौधारोपण अभियान में सिविल सोसायटी को भी शामिल किया जाय। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद मंझनपुर में उपवन की स्थापना के लिए डी.पी.आर. तैयार कर शीघ्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

जिलाधिकारी ने जिला गंगा समिति की बैठक के दौरान अधिशासी अधिकारी, दारा नगर को क्यू.आर.टी. टीम बनाकर गंगा घाट पर गंदगी फैलाने वालों को जागरूक किया जाय एवं जुमार्ना भी लगाया जाय। घाट की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय। घाट पर बैठने आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करा लिया जाय। उन्होंने सदस्य जिला गंगा समिति, विनय पाण्डेय के अनुरोध पर अधिशासी अधिकारी को हनुमान घाट पर विद्युत शवदाह गृह बनाने व गंगा आरती की सामग्री रखने के लिए स्टोर रूम बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नवरात्रि के अवसर पर भव्य एवं व्यवस्थित कार्यक्रम आयोजित कराने के भी निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशानुसार महिला जनसुनवाई 11 मार्च को

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशानुसार उ.प्र. राज्य महिला आयोग द्वारा महिला उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाये जाने तथा आवेदक/आवेदिकाओं की सुगमता के दृष्टिगत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में महिला जनसुनवाई की जा रहीं है।

उ.प्र. राज्य महिला आयोग की मा. सदस्य प्रतिभा कुशवाहा दिनांक 11.03.2026 को पूर्वान्ह 11:00 बजे मां शीतला अतिथि गृह, सयारा पहुँचकर महिला उत्पीडन से सम्बन्धित यथा-दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बाल विवाह आदि से सम्बन्धित विभिन्न अपराधों/घटनाओं/शिकायतों की समीक्षा/महिला सुनवाई करते हुए महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के सम्बन्ध में महिला जनसुनवाई की जायेगी।

उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने जिलाधिकारी विशाख जी से मिलकर मिठाई ,कैटरिंग ,रेस्टोरेंट, होटल व्यापारियों को व्यवसायिक गैस सिलेंडर मिलने में आ रही परेशानियों से अवगत कराया

अपर जिलाधिकारी खाद्य एवं आपूर्ति से उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में मिला तथा उन्हें ज्ञापन सोपा

वैश्विक कारणो से उत्पन्न इस स्थिति के लिए उत्तर प्रदेश आदर्श कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी लखनऊ विशाख जी से मुलाकात की तथा उन्हें

मिलकर मिठाई ,कैटरिंग ,रेस्टोरेंट, होटल व्यापारियों को व्यवसायिक गैस सिलेंडर मिलने में आ रही परेशानियों से अवगत कराया देते हुए बताया इंडियन ऑयल , हिंदुस्तान पेट्रोलियम एवं भारत पैट्रोलियम कंपनियों से बात करके शीघ्र ही उचित समाधान निकाला जाएगा उन्होंने कहा घरेलू गैस सिलेंडर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है व्यावसायिक में थोड़ा

वैश्विक कारणो से उत्पन्न इस स्थिति के लिए उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने सभी व्यापारियों से सरकार एवं प्रशासन का सहयोग करने की अपील की तथा अफवाहों से बचने की अपील की तथा साथ ही साथ

व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने सभी व्यापारियों से सरकार एवं प्रशासन का सहयोग करने की अपील की तथा अफवाहों से बचने की अपील की तथा साथ ही साथ जिला प्रशासन से फूड सेक्टर के व्यापारियों के लिए शीघ्र उचित समाधान निकालने की मांग की

लखनऊ ,मार्च ,मंगलवार ,उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने आज सुबह

उसके बाद उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का प्रतिनिधि मंडल अपर जिलाधिकारी खाद्य एवं आपूर्ति ज्योति गौतम से मिला

तथा उनसे विषय की जानकारी प्राप्त की तथा उन्हें व्यापारियों की समस्याओं का ज्ञापन सौपा

अपर जिलाधिकारी खाद्य एवं आपूर्ति ज्योति गौतम ने व्यापारियों से इस विषय पर सहयोग की अपील की

उन्होंने व्यापारियों को जानकारी सा सबको संयम बरतना होगा फूड सेक्टर को सप्लाई में प्राथमिकता देने का प्रयास है

अपर जिला अधिकारी ने आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियो के प्रतिनिधि मंडल को बताया भारत सरकार की पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार व्यावसायिक से संबंधित कुछ गाइडलाइन है जिसके अंतर्गत प्रशासन कार्य कर रहा है

जिला प्रशासन से फूड सेक्टर के व्यापारियों के लिए शीघ्र उचित समाधान निकालने की मांग की

उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार के प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता के साथ प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अविनाश त्रिपाठी ,मिठाई एवं रेस्टोरेंट व्यापारी राजेश गुप्ता, फूड व्यवसाय से संबंधित मो.आदिल शामिल थे